Regarding closing down of schools in Chandauli district, Uttar Pradesh- laid

श्री वीरेन्द्र सिंह **(**चन्दौली**) :** भारत सरकार की नई शिक्षा व्यवस्था के तहत पहला प्रहार प्राथमिक शिक्षा से जुड़े विद्यालयों पर हुआ है । जहाँ पूर्व की सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमाम सुविधाओं की व्यवस्था की थी, यहाँ तक कि पाठशालाओं में बच्चों को आकर्षित करने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. से जुड़ी पुस्तकै, उनको पहनने के लिए यूनिफोर्म तथा बैठने के लिए टाट के स्थान पर फर्नीचर लगाकर साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ाने का कार्य किया था । पूर्व की सरकारों का ऐसा मानना था कि गरीबों, आदिवासियों के जीवन स्तर एवं सामाजिक स्तर में सुधार का एक मात्र साधन शिक्षा व्यवस्था है । यदि प्राथमिक शिक्षा में १०० बच्चों में से गरीबों और आदिवासियों के 10 बच्चे भी आगे बढ़ जाते है तो सरकार इसे अपनी सफलता मानती थी । परन्तु वर्तमान सरकार और आरएसएस के नीतियों ने गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का जो प्रयोग किया है, उससे समूचा देश चिंतित हैं । एक और आंकड़ा आ रहा है कि 2014 से 2024 के बीच लगभग 91,000 विद्यालयों को बंद कर दिया गया है । यह आंकड़ा कहाँ तक सही है इसकी भी जानकारी देने का कष्ट करें । हमारे देश का जनपद चंदौली जो उत्तर प्रदेश राज्य का एक आदिवासी एवं गरीब बाहुल्य क्षेत्र है तथा आकांक्षी जनपद भी है, वहां कितने विद्यालयों को बंद किया गया है अथवा मर्ज किया गया है तथा उसके स्थान पर गाँव के अन्दर ही देसी शराब की दुकानों को खोलकर उन गरीबों और आदिवासियों के जीवन को नारकीय बनाया जा रहा है । हम सरकार से मांग करते है कि इस नए प्रयोग के आदेश को तत्काल वापस ले ताकि गरीबों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके ।